भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2810
उत्तर देने की तारीख 20 दिसम्बर, 2023

घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन

2810. श्री कृष्णपालसिंह यादवः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) योजना के बजट परिव्यय सहित दूरसंचार पीएलआई योजना के तहत डिजाइन-आधारित विनिर्माण की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना के तहत घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय क्या हैं;

(ग) दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना (टीटीडीएफ) के तहत विशेष रूप से दूरसंचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पहल के समर्थन के संबंध में हुई प्रगति क्या है;

(घ) दूरसंचार क्षेत्र में नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए टीटीडीएफ के तहत उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे उपाय क्या हैं;

(ङ) क्या उन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार की कोई पहल/योजना है जहां स्थलीय कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) से (घ) सरकार भारत में संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार विनिर्माण इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दूरसंचार प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई हैं। इनका विवरण इस प्रकार से है:

<u>दूरसंचार क्षेत्र में पीएलआई:</u>

दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम जून, 2021 में शुरू की गई थी।

इसने बहुत कम समय में भारत में दूरसंचार उपकरणों के उत्पादन को प्रेरित किया है। इसका विवरण निम्नानुसार हैं:

- कुल 33 दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद।
- 4 से 7% तक का प्रोत्साहन।
- पहले 3 वर्षों के लिए एमएसएमई के लिए अतिरिक्त 1% का प्रोत्साहन।
- 'भारत में डिजाइन किए गए' उत्पादों के लिए अतिरिक्त 1% का प्रोत्साहन।
- 28 एमएसएमई सहित कुल 42 आवेदक कंपनियां।
- कुल वित्तीय परिव्यय: 12,195 करोड़ रुपये।

दूरसंचार क्षेत्र में पीएलआई की अब तक की उपलब्धियां:

	आवेदकों द्वारा कुल प्रतिबद्धता	31 अक्टूबर, 2023 तक
संचयी निवेश	4,014 करोड़ रुपए	2,725 करोड़ रुपए
वृद्धिशील बिक्री	2,37,807 करोड़ रुपए	38,999 करोड़ रुपए
अतिरिक्त रोजगार	44,494	15,561

- दूरसंचार पीएलआई स्कीम के तहत अब तक 8,804 करोड़ रुपये के उत्पादों का निर्यात किया जा चुका है।

<u>टीटीडीएफ:</u>

- सरकार ने दिनांक 01.10.2022 को दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीटीडीएफ) स्कीम शुरू की थी।
- टीटीडीएफ का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और सेवाओं के अनुसंधान और विकास को वित्त पोषित करना है।
- स्टार्ट-अप, एमएसएमई, शिक्षा जगत आदि से टीटीडीएफ स्कीम के तहत 405 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। उचित मूल्यांकन के बाद अब तक 266.05 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 8 आवेदनों को अनुमोदित किया गया है। इनमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और मल्टीप्लेक्सिंग के साथ एडवांस्ड ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस टेस्ट बेड और 6जी टेरा हर्ट्ज टेस्ट बेड स्थापित करना शामिल है।

<u>डीसीआईएस स्कीम:</u>

- सरकार ने स्टार्ट-अप/एमएसएमई द्वारा नवीन विचारों और ज्ञान को व्यवहार में लाने को बढ़ावा देने और समर्थन देने के लिए डिजिटल संचार नवाचार स्क्वायर (डीसीआईएस) स्कीम शुरू की है।
- सरकार ने इस स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान के रूप में अब तक 96 से अधिक स्टार्ट-अप/एमएसएमई को 74.7 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है।
- ये इनोवेटर्स बैकहॉल रेडियो और संचार प्रौद्योगिकियों, एलटीई एडवांस्ड, 5जी/6जी और फ्यूचर जेनरेशन एक्सेस टेक्नोलॉजीज, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स (एसडीएन) आदि पर काम कर रहे हैं।

भारत में निर्मित 5जी:

- भारत 14 महीने से भी कम समय में 4 लाख से अधिक साइटों को चालू करने के साथ विश्व में 5जी के तीव्रतम रॉल-आउट में सबसे आगे रहा है।
- 5जी के रॉल-आउट में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की एक बड़ी मात्रा 'भारत में निर्मित' है।

स्वदेशी 5जी विकसित करना

- आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी 4जी/5जी दूरसंचार स्टैक विकसित किया गया है और इसे बीएसएनएल नेटवर्क में स्थापित किया जा रहा है।

इकोसिस्टम का विकास:

भारत सरकार का लक्ष्य देश के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकोसिस्टम को व्यापक और गहन बनाने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन (जीवीसी) में भारत की भागीदारी बढ़ाना है।

सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई एलएसईएम और पीएलआई आईटी हार्डवेयर)
- इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट्स और सेमीकंडक्टर्स (एसपीईसीएस) के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु स्कीम
- संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर 2.0 (ईएमसी 2.0)
- इसके अलावा, सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया था, इसके अंतर्गत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्स की स्थापना हेतु स्कीम, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर्स फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स फैब एवं सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग (एटीएमपी)/आउटसोर्सड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (ओसैट) और डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) संबंधी स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

सरकार की पहल के प्रभाव:

- इन उपायों के परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का घरेलू उत्पादन वर्ष 2014-15 में 1,80,454 करोड़ रुपये (29.8 बिलियन अमरीकी डालर) था जो अब बढ़कर वर्ष 2022-23 में 8,22,350 करोड़ रुपये (102 बिलियन अमरीकी डालर) हो गया है।
- इसके अलावा सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत पहली सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण साणंद, गुजरात में शुरू हो गया है।
- एक प्रमुख सेमीकंडक्टर कंपनी ने बेंगलुरु में अपना सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर डिजाइन सेंटर शुरू किया है।

- एक अन्य प्रमुख सेमीकंडक्टर कंपनी ने सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में कुशल इंजीनियरों के एक बड़े पूल को प्रशिक्षित करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर कार्य किया है।
- इसके अलावा मोबाइल उत्पादन वर्ष 2014-15 में 18,900 करोड़ रुपये था जो अब बढ़कर वर्ष 2022-23 में 3,50,000 करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 2014 में लगभग 78% आयात निर्भरता की स्थिति से भारत अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां भारत में बेचे जाने वाले सभी मोबाइल का 99.2% 'भारत में निर्मित' है।

(ङ) और (च) सरकार भारतनेट परियोजना के माध्यम से उन क्षेत्रों में सेटेलाइट के माध्यम से कनेक्टिविटी उपलब्ध करा रही है जहां स्थलीय स्तर पर कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। भारतनेट चरण-II में 5,166 ग्राम पंचायतों को सेटेलाइट के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा सरकार ने सेटेलाइट कनेक्टिविटी के माध्यम से उच्च गति डेटा सेवाएं प्रदान करने के लिए दो कंपनियों को एकीकृत लाइसेंस के अंतर्गत ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (जीएमपीसीएस) प्राधिकार जारी किया है।

*****